

विचार

नक्सलियों के खिलाफ चल रही निर्णायक मुहिम के मिलने लगे हैं बेहतर नतीजे

आमतौर पर नक्सली, आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड के मास्टरमाइंड अपने प्रेरणा के साथ भारतीय गणतंत्र के लिए चुनौती समझे जाते हैं। इसलिए सुरक्षाबलों ने 76वें गणतंत्र दिवस से महज कुछ दिन पहले नक्सलियों के खिलाफ जो निर्णायक कार्रवाई करते हुए, अंतरराज्यीय ऑपरेशन चलाए हैं और एक दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है, वह तिरंगे और संवेदनशील गणतंत्रिक व्यवस्था को सच्ची सलामी है। इसलिए देशवासियों की अपेक्षा है कि सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई और अधिक तेज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही हम उनके नापाक हैंसले को तोड़ सकते हैं। देखा जाए तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय थल या समुद्री सीमा से सटे प्रदेश हों या हमारे आंतरिक प्रदेश, यहां पर नक्सलियों, आतंकवादियों और अंडरवर्ल्ड सरगनाओं की मौजूदगी और उनके मार्फत जब-तब होते रहने वाली हिंसात्मक घटनाएं एक ओर जहां शासन व्यवस्था और अमनप्रसंद लोगों को मुंह चिढ़ाती हैं, वहां दूसरी ओर धनी लोगों के भयादोहन का कारण भी बनती है। चूंकि अवैध मानव व वस्तु तस्करी, डग्स सिंडिकेट, अवैध हथियारों के कारोबार, फिरौती, विवादास्पद सम्पत्तियों की खरीद-फरोख आदि से इनके तार जुड़े होते हैं, इसलिए सफेदपोश नेताओं-समाजसेवियों-कथित अधिकारियों-उद्योगपतियों आदि के माध्यम से इनके सरगना भी परस्पर मिले हुए होते हैं। आम धारणा रही है कि इनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई इसलिए भी नहीं हो पाती है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों और स्थानीय नेताओं से इनकी गुप्त सांठगांठ रहती है। और यही इनके तार कथित राष्ट्रीय नेताओं और अर्बन नक्सलियों-अपराधियों-आतंकवादियों के सिंडिकेट तक से जोड़ते हैं। यही वजह है कि प्रशासन भी सियासी कारणों के चलते इनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं कर पाता है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, पंजाब से लेकर उत्तर-पूर्वी राज्यों की आतंकी घटनाएं हों, या झारखण्ड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार की नक्सली घटनाएं, या फिर बड़े महानगरों से लेकर जिलास्तरीय शहरों की अंडरवर्ल्ड वारदातें, इनके तार परस्पर जुड़े बताए जाते हैं। कहना न होगा कि इनमें से कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की मजबूती के पीछे भी इनकी राष्ट्रियों सोच होती हैं, जिन्हें बरास्ता नेपाल, पाकिस्तान व चीन का भी संरक्षण हासिल होता है। वहीं, कांग्रेस समेत कई बड़े क्षेत्रीय दल भी इनके नेक्सस के समक्ष घटने टेक चुके हैं। जबकि इन सभी बातों से उलट केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी भाजपा नीत एनडीए की सरकार और उड़ीसा-छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र की भाजपा प्रदेश सरकारों की संगठित अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रोत्साहित होकर सरकार नक्सलियों-दुर्वात अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करन का जो बीड़ा उठाया है, उसकी एक झालक ताजा कार्रवाई से मिलती है।

गौरतलब है कि भारत में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को एक और बड़ी सफलता तब मिली, जब गत दिनों ऑडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर क्षेत्र में केंद्रीय रिकर्व पुलिस बल छत्तीसगढ़ के एसओजी (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) और ऑडिशा पुलिस के ज्वाइट ऑपरेशन के दौरान 14 नक्सलियों को मार गिराया गया।

कांग्रेस की विभाजनकारी राहों से जुड़े खतरे

ललित गर्ग

कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा से विभाजनकारी रही है। इनका एजेंडा ही रहा है देश में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बंटवारा करके अराजकता का माहौल बनाना। इसके लिये वह कभी संविधान को खतरे में बताती है तो कभी जातिगत जनगणना की मांग करती है। एक बार फिर डॉ. भीमराव आंबेडकर की जन्मस्थली महू में रैली के दौरान कांग्रेस ने जिस तरह इस पर जोर दिया कि संविधान पर हमला किया जा रहा है और महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। उससे उसकी विचारशून्यता एवं राजनीति अपरिपा ता ही प्रकट नहीं हो रही है, बल्कि देश को बांटने की मानसिकता भी उजागर हो रही है।



यह कांग्रेस के रणनीतिकार एवं नेता यह समझ रहे हैं कि वे संविधान के संदर्भ में भय का भूत खड़ा करने और भाजपा एवं संघ के नेताओं के बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश करने से देश की जनता को उग्राह करने, बराताने में समर्थ हो जाएंगे तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। उलटे इस क्रम में कांग्रेस की विश्वसनीयता और अधिक गिर सकती रही है और वह हास्यास्पद स्थिति का शिकार होकर अपनी राजनीतिक जमीन को कमज़ोर ही कर रही है ऐसा हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनावों में हुआ है और अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी ऐसे ही होते हुए दिख रहे हैं।

संविधान के खतरे में होने के कांग्रेस के द्वारा का लाभ भले ही कुछ सीमा तक लोकसभा चुनाव मिला हो, लेकिन हर बार मतदाता ऐसे नारों एवं दृष्टिकोण के असली धर्म-स्त्रृति के साथ राजनीतिक जमीन को जारी रखने के लिए अपनी राह चलने को बेताब है। लोकसभा चुनाव में भी एक समय ऐसा था, जिसके लिए एकमात्र आधार जाति में होती है तो कहीं पिछड़ी जाति में। जाति जनगणना करने के बाद भी उसके आंकड़े सार्वजनिक करना सही नहीं समझा था। क्योंकि कई ऐसी जातियां हैं, जिनकी एक राज्य में सामाजिक और अधिक हैसियत दूसरे राज्य से बिल्कुल भिन्न है। इन्हीं नहीं, कहीं उनकी गिनती अनुसूचित जाति में होती है तो कहीं पिछड़ी जाति में। जाति जनगणना करने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि पिछड़ीजन का एकमात्र आधार जाति है। एक समय ऐसा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज शहरों में किसी को इससे मतलब नहीं कि कौन किस जाति का है। जाति जनगणना करने का मतलब होगा देश को फिर से जातीय विभाजन की ओर ले जाना। इससे बचने में ही समझदारी है।

कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस गांधी के अनुसार तो खत्म नहीं हुई लेकिन देश में विभाजनकारी नीति के कारण जनता द्वारा नकारी जा रही है, खत्म होने के कारण पर पहुंच रही है।

कांग्रेस भारत की 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' की भावना को दबा रही है, सनातन परंपरा को दबा रही है। अनेक वर्षों तक दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस सत्ता में वापस आने के लिए इनी बेचैन है कि वो हर दिन नफरत, द्वेष एवं धृणा की राजनीति कर रही है। कांग्रेस सांसदायिकता और जातिवाद के विष को दिल्ली चुनाव में भी उड़ल रही है। हिंदू समाज को तोड़ना और उसे अपनी जाति को फॉर्मल बनाना ही कांग्रेस की राजनीति का अधार है और यही उसके रसातल में ले जा रहा है। कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग भी उसकी विभाजनकारी नीति को ही दर्शाती है। मोदी सरकार जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। सरकार के सामने समस्या केवल यह नहीं है कि जनगणना शीघ्र कराई जाए बल्कि मूल समस्या यह है कि कांग्रेस की जातिगत जनगणना पर जोर दे रही है, जो केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के इरादे से की जा रही है। जातिगत जनगणना का उद्देश्य समाजों को चुनावी लाभ के लिए जातियों में गोलबंद करना और जातिगत आकर्षण को तूल देकर बोटबंक की राजनीति को धार देना है। इसकी पृष्ठी विशेष नेताओं और विशेष रूप से कांग्रेस जातिगत जनगणना पर जोर दे रही है।

यह सही है कि भारतीय समाज जातियों में विभाजित रहा है, लेकिन अब जब यह विभाजन लगातार कर रहा है, तब जाति जनगणना कराकर जाति की राजनीति करने वालों को सामाजिक विभाजन का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह जातीय वैमनस्य को ही हवा देगा और इससे विभाजनकारी प्रवृत्तियों के सिर उठाने का ही खतरा है। जातिगत जनगणना बेहद जिले होने के साथ विभाजनकारी भी है। यही कारण है कि 2011 में मनमोहन सिंह के लिए जनगणना कराने के बाद भी उसके आंकड़े सार्वजनिक करना सही नहीं समझा था। क्योंकि कई ऐसी जातियां हैं, जिनकी एक राज्य में सामाजिक और अधिक हैसियत दूसरे राज्य से बिल्कुल भिन्न है। इन्हीं नहीं, कहीं उनकी गिनती अनुसूचित जाति में होती है तो कहीं पिछड़ी जाति में। जाति जनगणना के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि पिछड़ीजन का एकमात्र आधार जाति है। एक समय ऐसा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज शहरों में किसी को इससे मतलब नहीं कि कौन किस जाति का है। जाति जनगणना कराने का मतलब होगा देश को फिर से जातीय विभाजन की ओर ले जाना। इससे बचने में ही समझदारी है।

कांग्रेस एवं विशेष दलों का मोदी और भाजपा के विरोध के अलावा कोई साजा उद्देश्य नहीं है, उलटे उनमें दलगत हितों और महात्माकांशों का तल्ख टकराव है। दो लोकसभा चुनावों में धूशीये पर रहे विशेष दल तीसरे चुनाव के लिए एक साथ तो आए, पर मकाद सपा-न होने पर वापस अपनी-अपनी राह चलने को बेताब है। लोकसभा चुनाव में भी बंगाल, केरल और पंजाब में मिर दल आपस में ही जोर आजमाइश कर रहे थे। अब दिल्ली में भी कांग्रेस और आप अलग-अलग ताल ठोकते दिख रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के तेवरों से साफ है कि मोदी का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में नाकामी का बाद उसे शायद अपने पुनरुत्थान के लिए दिल्ली के चुनाव को आधार जाता रहा। तेवरों को एकमात्र आधार जाति है। दिल्ली के चुनावों के दूरुस्थ अन्यतरी विभाजनकारी नीति को बाट आ-पार तक पहुंच गई। यह एक पुरानी कहावत है कि देश जैसी सरकार के बायां होता है, वैसी ही सरकार बनायी जाती है। कांग्रेस ने एक बदल को बाल्क इंडिया गर्भव बनाया है, लेक

सोलापुर में जीवी सिंड्रोम के 9 नए केस, 1 मौत

मंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के सोलापुर में सोमवार को गुडलेन-बैरे सिंड्रोम के 9 और केस सामने आए। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इन मरीजों में 73 पुरुष और 37 महिलाएं हैं, जबकि 17 मरीज वैटलेटर सपोर्ट पर हैं। इससे पहले 26 जनवरी को सोलापुर के रहने वाले 40 साल के शख्स की मौत इसी जीवी सिंड्रोम के कारण हुई थी, इसकी पृष्ठी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अवितकर ने भी कोकी। सोलापुर सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. संजीव ठाकुर के मुताबिक मरीज को संसं पफलने, निचले अंगों में कमजोरी और दस्त जैसे लक्षण थे। उसे 18 जनवरी से लगातार वैटलेटर सपोर्ट पर था। डीन ने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए क्लिनिकल पोस्टस्टार्टम किया गया। जिसमें वजह जीवीएस सिंड्रोम बताइ गई। जांच के लिए ब्लड सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायोरोलॉजी भेजा गया है शहर के अलग-अलग हस्पतों से 34 वाटर सैंपल भी कैमिकल और वायोलॉजिक एनालिसिस के लिए पल्टवाल हेल्थ लैब भेजे गए। इनमें से सात सैंपल में पानी के दर्खियों की सूचना मिली है। गौरतलब है कि पुणे में 9 जनवरी को अस्पताल में मरीज लक्षणों पर आया था, यह पहला केस था। 19 दिन में एक्टिव केस बढ़ गए हैं।

बागपत में जैन धर्म के महोत्तम में हादसा, 7 मौतें

बागपत (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के बागपत में मंगलवार को जैन समुदाय के निर्णय महोत्तम के दौरान हादसा हो गया। यहाँ 65 फीट ऊंचे मंच की सीढ़ियां टूट गईं। इससे कई श्रद्धालुएं एक दूसरे पर गिरते चले गए। भगदड़ जैसे हालात हो गए। हादसा में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जबकि 80 से अधिक लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। स्थानीय लोगों ने घटना में खुन से लथपथ श्रद्धालुओं को ढेले से अस्पताल पहुंचाया। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया। रातोंद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। हादसा बागपत शहर से 20 किमी दूर बड़ी तहसील में सुख 7 से 8 बजे के बीच हुआ। महोत्तम में आदिनाथ भगवान को प्रसाद चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था। 65 फीट ऊंची लाकड़ी का मंच बनाया था। उस पर भगवान की 4-5 फीट ऊंची प्रतिमा रखी थी। श्रद्धालु भगवान तक पहुंचने के लिए मचन्नुमा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। वजन बढ़ने से पूरा मचान नीचे गिर गया।

यमुना विवाद, हरियाणा सीएम बोले- बयान पर माफी मांगें केरजीवाल

चंडीगढ़ (एजेंसी)। दिल्ली के पर्व सीएम अरविंद केरजीवाल के यमुना नदी में जहर मिला। जाने के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उड़वे चुनौती दी दी। सैनी ने कहा- वह अपने बयान के लिए हरियाणा और दिल्ली के लोगों से तुरंत माफी मांगें, नहीं तो हम उनके खिलाफ मानहानि का क्षेत्र करेंगे। सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोग यमुना की पांडा करते हैं। वे भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे। सैनी के बयान के बाद केरजीवाल ने कहा- सैनी साहब पानी के ऊपर राजनीति ना करो, पापा चेहरा तुमको। लोगों की बुझाएं रहिए। केस करना है तो करो। वैसे भी कोई कसर छोड़ी है क्या? अब क्या फांसी पर चढ़ाओगे? उठर, मंगलवार को दिल्ली की छूट आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर लिखकर पानी रोकने की मांग की है।

दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरी, 3 की मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के उगाड़ी इलाके में सोमवार शाम 6.30 बजे 4 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। घटना में 2 लड़कियों समेत 3 की मौत हो गई। लड़कियों की पहचान साधना (17) और राधिका (7) के रूप में हुई है जबकि तीसरे व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई गई है। पुलिस के मुताबिक 12 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है।

घायलों का इलाज जारी है। मलबे में अभी भी और लोग फंसे हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस, फायर बिग्रेड, डीडीएमए और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। पुलिस के मुताबिक बुराड़ी के आंखर कप्लिक स्कूल के पास नई बिल्डिंग तैयार की जा रही थी।

